(ख) ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीणों को अन्य राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त दी गई अन्य विशेष सुविधायें क्या हैं;

(ग) राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर और जैसलमेर जो देश में सबसे अधिक पिछड़े हुये जिले हैं और जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था भिन्न-भिन्न है, में उनके विभाग द्वारा ग्रामीण बैंक खोलने में देरी के कारण क्या हैं; और

(घ) इन पिछड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जरूरी आवश्यकताओं को वहां ग्रामीण बैंक खोल कर कब पूरा किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्तमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (घ). इस समय राजस्थान राज्य में चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं जिनके कार्यक्षेत्र के भीतर आठ जिले आते हैं । नीचे की सारणी में इन बैंकों का ब्यौरा दिया गया है :—

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्थापना की तारीख	व्याप्त जिले
1. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर	20-10-1975	1. जयपुर 2. नागौर
2. मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली	6-9-1976	1. पाली 2. सिरोही 3. जालोर
3. शेखावाटी ग्रामीण बैंक, सीकर	7-10-1976	1. सीकर 2. झुनझुनु
4. मरुक्षेत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चूरु		1. चूरु

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना खासकर ग्रामीण समुदाय विशेषत: छोटे/सीमान्तिक किसानों, खेतिहर मजदूरों और देहाती कारीगरों की ऋण संबन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है । इन बैंकों के स्थानों का चयन करने के लिए जिन सामान्य सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है उनमें ऋण-अंतराल, सहकारी ऋण ढांचे की स्थिति तथा वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के जाल के फैलाव आदि जैसे पहलू शामिल होने हैं । ये बैंक अपने परिचालन क्षेत्रों में लक्षित समूहों के लिए युक्तिसंगत ब्याज दरों पर ,जो सहकारी बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दरों के समतुल्य रखी गयी हैं, ऋण का प्रबंध करने के अलावा, जमा रकमों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की तुलना में आधा प्रतिशत अधिक ब्याज भी देते हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने के लिए स्थानों का सुझाव, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों विषयक संचालन समिति देती है और राज्य सरकारों द्वारा किये गए प्रस्तावों को ध्यान में रखा जाता है । इस समय कुछ अन्य जिलों जैसे भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और बूंदी के संबंध में प्रस्ताव किये गए हैं लेकिन जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Withdrawal of Concessional Rates of Duty Applicable to Khandsari Units

*173. SHRI RAJESH KUMAR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Central Government have recently withdrawn the concessional rates of duty applicable to Khandsari units working under the normal procedure and have also revised the duty on Khandsari sugar and if so, the reasons thereof;

(b) the number of persons thrown out of employment as a result thereof; and

(c) whether any alternative arrangements have been made by Government for their employment and if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): (a) Yes. Sir. Having regard to the prevailing prices of Khandsari sugar, and the need to ensure adequate supply of cane to the various sctors of the sugar industry in order to maximise sugar production, the excise duty on Khandsari sugar has been revised.

(b) Government consider that the increase in the duty will not lead to any unemployement.

(c) In view of the reply to (b) above, the question does not arise.

Withdrawal of Countervailing Duties Imposed by U.S. on India's Textile Exports

*174. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the counterviling duties imposed by USA on India's textile exports have been withdrawn by now;

(b) whether all the textile cargo held up at various Americon Ports had been cleared up by now; and

(c) whether this withdrawal applies to other exports from India?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes, Sir. Countervailing duties imposed provisionally on certain textile products have been withdrawn.

(b) Government have no information that any shipments of textiles were detained on this account.

(c) No, Sir.

Invitation to Oil Nations for Investment in India

*175. SHRI RAJESH KUMAR SINGH:
SHRI JANARDHANA POOJARY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government of India have invited oil Nations to invest money on a priority basis in the country;

(b) if so, the names of the countries who have shown their willingness to invest in this country; and

(c) the foreign exchange which is likely to be invested during the next five years under this invitation?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): (a) and (b). Taking into account the interest shown by some Oil Exporting Developing Countries for investment in India Government have decided to provide the following investment facilities:

(i) Investment from oil exporting developing countries may be permitted in new companies even if it is in the nature of portfolio investment.

(ii) Such investments should not exceed 40 per cent in the equity.

(iii) The new companies should be export-oriented or should undertake manufacturing activities covered under Appendix I of the Industrial Policy of 1973.

(iv) Investment on the aforesaid pattern may be allowed in hotels.

(v) Investment may also be allowed in new hospital projects and such hospitals should have adequate provision for out door and emergency medical